



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57774-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत आपराधिक अपील (दोषपूर्ण) संख्या - 47/2026

रामपाल

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: अनिल कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय,

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II,

(दाण्डिक प्रकीर्ण विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026 पर आदेश)

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत वर्तमान अपील अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 12, मेरठ द्वारा सत्र विचारण संख्या 1211/2010 (मुकदमा अपराध संख्या 281/2003, धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना इंचौली, जनपद मेरठ से उत्पन्न) के साथ-साथ सत्र विचारण संख्या 141/2025 एवं सत्र विचारण संख्या 284/2025 (मुकदमा अपराध संख्या 104/2004, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना इंचौली, जनपद मेरठ से उत्पन्न) में पारित दोषमुक्ति आदेश दिनांक 29.9.2025 को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

अपील समय सीमा से 58 दिन की देरी से दायर की गई है।

विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दायर शपथ पत्र में विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है।

विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील दायर करने में हुए विलम्ब को एतद्वारा क्षमा किया जाता है।

कार्यालय अपील को नियमित संख्या आवंटित करे।

अपील पर आदेश

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दिनांक 09.11.2003 को सुबह लगभग 08:00 बजे, राकेश, यानी मृतक, लौकी लाने के लिए तोहफापुर गांव गया था। हालांकि, जब वह 13.11.2003 तक नहीं लौटा, तो 13.11.2003 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14.11.2003 को मृतक का शव धर्मपाल यादव के खेत में मिला। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा दिनांक 14.11.2003 को हरिश्चंद्र पुत्र नुन्नू, सावित्री देवी पत्नी हरिश्चंद्र और हुकमी पुत्र नुन्नू के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा अपराध संख्या 281/2003 पंजीकृत करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उपरोक्त व्यक्तियों को संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया था कि उपरोक्त व्यक्तियों ने हरिश्चंद्र के साले को जेल से छुड़ाने के लिए मृतक से 2,500/- रुपये की मांग की थी, लेकिन मृतक ने इनकार कर दिया था, इसलिए उपरोक्त व्यक्तियों ने मृतक की हत्या कर दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई रामपाल द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात, अभियोजन पक्ष का दावा है कि अपराध का हथियार, यानी एक चाकू, किरनी उर्फ किरण पाल, यानी विपक्षी संख्या 2 के प्रकटीकरण पर बरामद किया गया था और इसके बाद, विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा अपराध संख्या 104/2004 भी पंजीकृत किया गया था।

पंचायतनामा तैयार किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिनांक 15.11.2003 को किए गए पोस्टमार्टम में नोट किया गया कि मृतक की गर्दन पर 15x10 सेमी के फटे हुए घाव थे जो हड्डी तक गहरे थे। शव सड़ने की अवस्था में भी था और संबंधित डॉक्टर की राय थी कि मृत्यु पोस्टमार्टम से 3 से 5 दिन पहले हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर द्वारा सिद्ध किया गया था जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्ल्यू-4 के रूप में परीक्षण किया गया था।

विपक्षीगण के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया और मामला विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद विपक्षीगण के विरुद्ध धारा 302/201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सत्र विचारण संख्या 141/2025 और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत सत्र विचारण संख्या 284/2025 पंजीकृत किए गए। हुकमी और सावित्री देवी को आरोप पत्र से बाहर कर दिया गया था। विपक्षीगण ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का विकल्प चुना।

अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस साक्ष्य पर आधारित था कि अभियुक्तों को अभियोजन साक्षियों द्वारा दिनांक 9.11.2003 को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, पीडब्ल्यू-6 और पीडब्ल्यू-5 के समक्ष अभियुक्तों का न्यायतः इकबालिया बयान था, विपक्षी संख्या 2 के प्रकटीकरण पर अपराध का हथियार बरामद हुआ था और अभियुक्तों के पास मृतक की हत्या करने का मकसद था।

विचारण न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य पर अविश्वास जताते हुए माना कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, इसलिए अभियुक्तों / विपक्षीगण को दोषमुक्त कर दिया। अतः प्रथम सूचनाकर्ता, जो मृतक का भाई भी है, द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत वर्तमान अपील की गई है।

जहाँ तक अभियोजन के इस दावे का संबंध है कि अभियुक्तों को दिनांक 9.11.2003 को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, अभियोजन ने उपर्युक्त तथ्य को सिद्ध करने के लिए पीडब्ल्यू-7, पीडब्ल्यू-10 और पीडब्ल्यू-2 का परीक्षण किया। विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू-7 और पीडब्ल्यू-10 की गवाही को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उनकी गवाही में कई बड़े विरोधाभास थे और आगे, पीडब्ल्यू-7 और पीडब्ल्यू-10 की गवाही में अतिरंजना और सुधार प्रतीत होते हैं। पीडब्ल्यू-7 मृतक का साला है। अपनी गवाही में, गवाह ने कहा कि उसने मृतक को हुकमी, हरिश्चंद्र, किरण पाल और सावित्री देवी (हरिश्चंद्र की पत्नी) के साथ दिनांक 9.11.2003 को सुबह लगभग 10:00 बजे देखा था। गवाह

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा यह कहा गया है कि उसने अभियुक्तों को मृतक के साथ देखने के चार दिन बाद भूरे को इस तथ्य का खुलासा किया था। भूरे मृतक का भाई है और विचारण के दौरान पीडब्ल्यू-2 के रूप में उसका परीक्षण किया गया था। गवाह द्वारा यह भी कहा गया है कि वह भूरे के साथ अभियुक्त और सावित्री देवी के साथ-साथ हुकमी के घर गया था लेकिन उपरोक्त व्यक्ति अपने घर पर नहीं मिले थे। अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-10, जो मृतक की बहन है, ने कहा कि उसने मृतक को अभियुक्तों के साथ-साथ हुकमी और सावित्री देवी के साथ दिनांक 9.11.2003 को सुबह लगभग 08:00 बजे देखा था। गवाह ने यह भी कहा है कि उसने अगले दिन रामपाल को उक्त तथ्य के बारे में सूचित किया था।

अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-2 ने कहा कि उसे अमी चंद ने बताया था कि अमी चंद ने मृतक को अभियुक्तों के साथ-साथ हुकमी और सावित्री देवी के साथ देखा था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमी चंद को मामले में गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा हरिश्चंद्र और हुकमी पर आरोप तय नहीं किए गए थे और हुकमी तथा सावित्री देवी के विरुद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू-7 और पीडब्ल्यू-10 की गवाही पर इस आधार पर अविश्वास किया है कि दोनों गवाहों ने अलग-अलग समय बताया है जब उन्होंने दिनांक 9.11.2003 को मृतक को अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखा था। इसके अलावा, गवाहों की गवाही यह भी दर्शाती है कि उन्होंने मृतक के भाइयों, यानी प्रथम सूचनाकर्ता और पीडब्ल्यू-2 को बताया था कि मृतक को उनके द्वारा दिनांक 9.11.2003 को अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखा गया था। यह जानकारी गुमशुदगी की रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले दी गई थी। हालांकि, दिनांक 13.11.2003 को दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट और दिनांक 14.11.2003 को पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपर्युक्त तथ्य का उल्लेख नहीं है, भले ही, पीडब्ल्यू-7 की गवाही के अनुसार, प्रथम सूचनाकर्ता पीडब्ल्यू-7 की सूचना पर मृतक की तलाश करते समय अभियुक्तों के घर गया था। इसके अलावा, पीडब्ल्यू-10, जो मृतक की बहन है, ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में विवेक को उपर्युक्त जानकारी का खुलासा नहीं किया था। विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त तथ्य और इस तथ्य को नोट करने के बाद कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और गुमशुदगी की रिपोर्ट में उपर्युक्त तथ्य का उल्लेख नहीं है, गवाहों के इस दावे पर अविश्वास किया है कि उन्होंने मृतक को दिनांक 9.11.2003 को अभियुक्तों की संगति में अंतिम बार देखा था। उपरोक्त के अलावा, विचारण न्यायालय ने इस आधार पर 'अंतिम बार देखे जाने' के साक्ष्य को खारिज कर दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मृत्यु पोस्टमार्टम की तारीख से 3 से 5 दिन पहले हुई थी। शव परीक्षा दिनांक 15.11.2003 को की गई थी। अभियोजन साक्षी द्वारा यह दावा किया गया है कि मृतक को उनके द्वारा दिनांक 9.11.2003 को अभियुक्तों की संगति में अंतिम बार देखा गया था। शव परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु जल्द से जल्द 10.11.2003 को हुई होगी, जो अभियोजन साक्षी द्वारा मृतक को अभियुक्तों के साथ देखे जाने के दावे के कम से कम 24 घंटे बाद का समय है। उपरोक्त तथ्य अभियोजन द्वारा अंतिम बार देखे जाने के दावे को संदिग्ध बनाता है और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए सही रूप में इस पर भरोसा नहीं किया है।

जहाँ तक अभियोजन के इस दावे का संबंध है कि अभियुक्तों ने पीडब्ल्यू-6 के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया था, अभियुक्तों को फंसाने के लिए उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-6 ने कहा कि अभियुक्तों ने पीडब्ल्यू-6 के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया था और यह भी कहा है कि जब अभियुक्तों ने पीडब्ल्यू-6 के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया था तब

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीडब्ल्यू-5 वहां उपस्थित था। अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-5 ने अभियुक्तों द्वारा कथित इकबालिया बयान को सिद्ध नहीं किया है और इस बात से इनकार किया है कि उसने विवेचक के समक्ष उक्त तथ्य को तब स्वीकार किया था जब विवेचक द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उसका बयान दर्ज किया जा रहा था। विचारण न्यायालय ने अभियोजन मामले पर विश्वास करने के लिए पीडब्ल्यू-6 की गवाही पर भरोसा करने से सही रूप में इनकार कर दिया है।

जहाँ तक अपराध के हथियार की बरामदगी का संबंध है, विचारण न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि कथित बरामदगी घटना के चार महीने बाद की गई थी। बरामदगी को पीडब्ल्यू-8 द्वारा सिद्ध किया गया है लेकिन पीडब्ल्यू-2 द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है जो बरामदगी मेमो का गवाह भी है। अपनी गवाही में, पीडब्ल्यू-8 ने कहा है कि पीडब्ल्यू-2 मौके पर तब मिला था जब वह साइकिल से आ रहा था और वह गवाह (जो एक पुलिस अधिकारी है) की जीप में बरामदगी के स्थान पर नहीं गया था। उक्त तथ्य पीडब्ल्यू-2 की गवाही के साथ असंगत है जो कहता है कि वह पीडब्ल्यू-8 के वाहन में मौके पर गया था। बरामद हथियार को एफ.एस.एल. जांच के लिए नहीं भेजा गया था और अभियुक्त / विपक्षी संख्या 2 के प्रकटीकरण बयान के अलावा, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पुलिस द्वारा बरामद हथियार का उपयोग अपराध में किया गया था। पीडब्ल्यू-2 इस बार में भी अनभिज्ञता जताता है कि बरामद हथियार लोहे का बना था या पीतल का। पीडब्ल्यू-2 ने अपनी गवाही में यह भी कहा है कि उसने बरामदगी मेमो पर बिना उसे पढ़े हस्ताक्षर किए थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विपक्षी संख्या 2 के प्रकटीकरण पर हथियार की कथित बरामदगी के बाद कोई नमूना मोहर तैयार नहीं की गई थी जिसे विवेचक द्वारा सील किया गया था। मामले के अभिलेख पर कोई नमूना मोहर उपलब्ध नहीं थी।

जहाँ तक मकसद का संबंध है, विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त आधार पर भी गवाह की गवाही पर अविश्वास किया है। जैसा कि पहले नोट किया गया है, सावित्री देवी पर आरोप नहीं लगाया गया है और उपर्युक्त मामले में कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

अभियोजन मामले में ऊपर नोट की गई कमियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं था। हमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई विषमता या कोई अन्य अवैधता नहीं मिली है। वर्तमान अपील में विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में तथ्य या कानून का कोई आधार नहीं बनता है।

उपरोक्त सभी कारणों से, हम मामले के अभिलेख को तलब करने के बाद अपीलार्थी के आग्रह पर साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करना उचित नहीं समझते हैं।

अपील को सरसरी तौर पर खारिज किया जाता है।

अपील को नियमित संख्या आवंटित करने के बाद और वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद फाइल को अभिलेख में भेज दिया जाए।

(डॉ. अजय कुमार-II, न्यायमूर्ति) (सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

सत्यम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"